# पश्चिमी यूपी में दो और औद्योगिक पार्क बनेंगे

**तैयारी**

- 'प्लेज' योजना में 11 निजी औद्योगिक पार्कों को अनुमति मिली है
- योजना के तहत मुरादाबाद और सहारनपुर में खुलेंगे उद्योग पार्क

लखनऊ, विशेष संवाददाता। एमएसमएमई सेक्टर के लिए यूपी में दो और औद्योगिक पार्क बनेंगे। 'प्लेज' योजना के तहत यह पार्क मुरादाबाद व सहारनपुर में बनेंगे। यहां लघु उद्योगों की स्थापना होगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

यहां जमीन चिन्हित कर ली गई है। अब यहां सरकार जमीन के आसपास पहुंच मार्ग व अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगी। इस योजना के जरिए नए निवेशकों को सहारनपुर व मुरादाबाद में अपने उद्योग लगाने के लिए जमीन का विकल्प उपलब्ध होगा। यहां औद्योगिक पार्क विकसित होने से उत्पादन बढ़ेगा साथ ही निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। यहां के स्थानीय स्तर पर कारीगरों को काम मिलेगा।

**अभी तक यहां प्लेज पार्क को मिली है मंजूरी :** पश्चिमी यूपी में बागपत, बरेली, गाजियाबाद व मेरठ में पहले से प्लेज पार्क पर काम चल रहा है। रुहेलखंड में शाहजहांपुर, मध्य यूपी में बाराबंकी, लखनऊ व पूर्वांचल में वाराणसी व चंदौली में प्लेज पार्क के तहत चिन्हित जमीन का विकसित किया जा रहा है जबकि झांसी व हापुड़ में प्लेज पार्क का काम काफी आगे बढ़ गया है।

पिछले दिनों लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने एमएसएमई विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत सिडबी इन पार्क की स्थापना में सहयोग करेगा। पिछले साल यूपी सरकार ने एमएसएमई उद्योगों के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपये के 9000 के एमओयू साइन किए थे। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में जमीन की दिक्कत इस योजना से कुछ हद तक दूर होगी।

**क्या है प्लेज पार्क :** प्लेज (प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फार डवलपमेंट आफ ग्रोथ इंजन) स्कीम योजना के तहत पास 10 से 50 एकड़ तक जमीन का मालिकाना हक रखने वाले निवेशक इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सरकार इस योजना के तहत किसी निजी कंपनी को प्रति एकड़ एक प्रतिशत ब्याज पर 50 लाख का कर्ज देती है। इस राशि से वह अपनी जमीन को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से विकसित करता है। बाद में तय समय में यह राशि सरकार को वापस की जाती है।

इसमें स्टांप ड्यूटी में सौ प्रतिशत छूट मिलती है। इस जमीन को निजी निवेशक अपने हिसाब से भूखंड निकाल कर निजी कंपनियों को बेचता है ताकि वह यहां पर उद्योग लगा सके। जमीन की कमी व महंगे दर के कारण निवेशकों के जमीन उपलब्ध कराने में काफी दिक्कत आती है। प्लेज योजना अब जोर पकड़ रही है। इस योजना से सरकार को जमीन इंतजाम कर निवेशकों को देना नहीं पड़ेगा।